

हाईकोर्ट ने वो कर दिखाया जो सरकार नहीं कर पाई : एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 रद्द की

हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि एस.आई. भर्ती परीक्षा 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार ही पुनः आयोजित की जाए

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 28 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यापक पेपर लीक और नकलबाजी के आरोपों को सही मानते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.) द्वारा एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द कर, महाधिवक्ता की राय के अनुसार 2021 की विज्ञप्ति में संशोधन कर पुनः आयोजित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार जुलाई 2025 में जारी नई विज्ञप्ति में भी संशोधन कर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 2021 की भर्तियों को भरने का प्रावधान कर सकती है।

हाईकोर्ट के आदेशानुसार पुनः आयोजित परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को आयु सम्बन्धी योग्यता में रियायत दी जाए, साथ ही सभी योग्य अभ्यर्थियों को 2021 में मिल रहे आरक्षण व अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा

■ हाईकोर्ट के आदेशानुसार पुनः आयोजित परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को आयु सम्बन्धी योग्यता में रियायत दी जाए, साथ ही सभी योग्य अभ्यर्थियों को 2021 में मिल रहे आरक्षणों व अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए।

■ अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की सरकारी सेवा को छोड़ा था और फिर एस.आई. भर्ती परीक्षा में चयनित हुए थे।

■ न्यायाधीश समीर जैन ने अपने आदेश में तत्कालीन आर.पी.एस.सी. अध्यक्ष संजय श्रौतिया समेत अन्य सदस्य, जिनमें बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, मंजू शर्मा, संगीता आर्या और जसवंत राठी पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन अफसरों ने व्यापक पेपर लीक को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई और आर.पी.एस.सी. की विश्वसनीयता को छलनी किया।

है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की सरकारी सेवा का छोड़ा था और फिर एस.आई. भर्ती परीक्षा में चयनित हुए

2025 तक योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश से वो कर दिखाया है जो पिछले डेढ़ वर्ष से राज्य सरकार करने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि, जैसा कि विदित है कि इस मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वी.के. सिंह, की देखरेख में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट दायर करी थी कि एस.आई. भर्ती-2021 में अपराधिक गिरोह शामिल थे, जिन्होंने आर.पी.एस.सी. के अध्यक्ष सहित छह सदस्यों के साथ मिलकर व्यापक पेपर लीक के षड्यंत्र को अंजाम दिया था और फिर चयनित अभ्यर्थियों से 'इंटरव्यू' में घूस के लिए अच्छे अंक देने का भी षड्यंत्र रचा था।

बताया जा रहा है कि इस मामले की शुरूआती जांच के दौरान स्वयं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिनेश पटनायक कैनडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त

नयी दिल्ली, 28 अगस्त। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश के. पटनायक को कैनडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि उनके शीघ्र ही पद भार ग्रहण करने की संभावना है।

पटनायक भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और वह स्पेन में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

उल्लेखनीय है कि कैनडा में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री

■ दो वर्ष पहले टूटो के शासनकाल में दोनों देशों में भारी तनाव के कारण कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर दिए गए थे।

नरेन्द्र मोदी और कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच गत जून में जी-7 की आउटरीच बैठक के दौरान हुई मुलाकात में संबंधों को सुधारने पर बनी सहमति के बाद की गयी है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दिल्ली और ओटावा में उच्चायुक्तों की बहाली का निर्णय लिया था।

खालिस्तानी संगठन से जुड़े हरदीप सिंह निज्जर की दो वर्ष पहले हुई हत्या को लेकर जस्टिन टूडो सरकार ने इसमें भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। भारत ने इससे साफ इंकार किया था (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘मैंने कभी नहीं कहा मैं 75 साल में रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को हो जाना चाहिए’

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल की आयु में रिटायर होने के विवाद पर यह टिप्पणी की

- संघ प्रमुख भागवत के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में देखा जा रहा है।
- ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितम्बर को और मोहन भागवत 11 सितम्बर को 75 साल के हो रहे हैं।
- संघ प्रमुख ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष के सम्बंध में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह भी कहा कि भाजपा व आरएसएस के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं है। हमें एक-दूसरे पर विश्वास है।

जाने हैं, हम चाहें या न चाहें। अगर मैं 80 साल का हूँ और संघ कहता है कि जाओ और शाखा चलाओ, तो मुझे करना ही होगा। संघ जो भी कहता है, हम करते हैं। यह किसी की सेवानिवृत्ति के लिए नहीं है। हम सेवानिवृत्त होने या काम करने के लिए तैयार हैं। जब तक संघ चाहता है।

उन्होंने कहा कि मैं शाखा चलाने में माहिर हूँ, भाजपा सरकार चलाने में माहिर है, हम एक-दूसरे को सिर्फ

सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम फैसला नहीं करते, अगर हमें फैसला करना होता तो क्या इसमें इतना समय लगता।

भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद के सवाल पर संघ प्रमुख ने कहा कि मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। हमारे यहां मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे पर विश्वास है...क्या भाजपा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘प्र.मंत्री मोदी की सतही विदेश नीति का देश को नुकसान ही हुआ’

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि, सरकार की मुस्कान, गले मिलने और “सेल्फी” लेने पर आधारित विदेश नीति, देश के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकी

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 अगस्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि सरकार देश की रक्षा करने में विफल रही है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जी.टी.आर.आई.) की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग एक प्रतिशत जीडीपी पर असर पड़ सकता है और इसका फायदा चीन को मिलेगा।

बुधवार से अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क लागू होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यापार समझौता न कर पाने और देश की रक्षा न कर पाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चेतावनी दी कि टैरिफ की पहली मार में कम से कम 10 सेक्टरों को 2.17 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि विदेश नीति के दिखावटी कार्यक्रम, मुस्कान, गले लगाना और सेल्फी, ने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया है। खड़गे ने कहा, “आपके प्यारे दोस्त

■ खड़गे ने इसी संदर्भ में यह भी कहा, कि “ट्रेड डील” (व्यापारिक समझौता) नहीं होने से 10 सेक्टरों में ही 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

■ भारत के “टैक्सटाइल उद्योग” में ही 5,00,000 नौकरियां खत्म हो जायेंगी। जैम्स व ज्वेलरी क्षेत्र में 1,50,000 से 2,00,000 नौकरियां कम हो जायेंगी, हीरे की कटिंग व पॉलिशिंग उद्योग में भी एक लाख वर्कर बेरोजगार हो जायेंगे।

“अबकी बार, ट्रंप सरकार” ने आज से भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। हमारे किसान, खासकर कपास के किसान, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आपने कहा था कि आप उनकी रक्षा करने के लिए कोई भी “निजी कीमत” चुकाने को तैयार हैं, लेकिन आपने उनके नुकसान को कम करने और आजीविका बचाने के लिए कुछ नहीं किया।”

उन्होंने कहा कि कई निर्यात-आधारित अहम सेक्टर, खासकर एमएसएमई, में बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान होगा।

खड़गे ने कहा कि “भारतीय वस्त्र निर्यात क्षेत्र में लगभग 5 लाख नौकरियों का नुकसान हो सकता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल है।”

उन्होंने बताया कि अगर शुल्क जारी रहा तो रत्न और आभूषण सेक्टर में भी 1,50,000 से 2,00,000 नौकरियों पर खतरा है। उन्होंने कहा, सौलद्र क्षेत्र में हीरे काटने और पॉलिश करने वाले करीब 1,00,000 मजदूरों की नौकरियां अप्रैल से ही जा चुकी हैं, जब अमेरिका ने 10 प्रतिशत बेस टैरिफ लगाया था।

उभरे हैं, जबकि पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची सबसे निचले स्थान पर हैं। गुरुवार को जारी राष्ट्रव्यापी सूचकांक में, 31 शहरों की 12,770 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट व महिला सुरक्षा सूचकांक 2025, के अनुसार जयपुर के साथ दिल्ली, पटना व कोलकाता महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित शहर हैं, वहीं, मुम्बई, कोहिमा, इटानगर आइजोल और भुवनेश्वर सर्वाधिक सुरक्षित माने गए हैं।

भारत ने ट्रंप की “टैरिफ दादागिरी” के जवाब में गिड़गिड़ाने की नहीं सामना करने की नीति फाइनल की

इस नीति के तहत भारत कोई अर्जी नहीं देगा कुछ रियायत करने की, और न ही इन्तज़ार करेगा ट्रंप में हृदय परिवर्तन होने का

■ भारत के नीतिकारों का मानना है, “डॉमैस्टिक कंज़प्शन” (देश की घरेलू डिमान्ड) का आज भी योगदान, जी.डी.पी. के आंकड़े में 61 प्रतिशत है, और कुछ और टैक्स आदि की रियायतें देकर भारत की “घरेलू डिमान्ड”, को और अधिक बढ़ाने की काफी गुंजाइश (स्कोप) है।

■ इसी दिशा में बढ़ते हुए, हाल ही में जी.एस.टी. का सरलीकरण करने की घोषणा की गई है, तथा दो ही “स्लैब” (वर्ग), 12 प्रतिशत व 18 प्रतिशत रह जायेंगे।

■ भारत का यह इतिहास रहा है कि जब भी विदेशी दबाव पड़ा है, भारत दबाव के आगे झुका नहीं। पं. नेहरू पर भारी दबाव था शीत युद्ध के जमाने में, अमेरिका का खेमा या रूस का खेमा जॉइन करने का, पर, उन्होंने “नॉन एलाइन्ड” (निर्मुक्त) रहने का निर्णय लिया। इंदिरा गांधी भी, 1971 के संकट के समय अमेरिका के दबाव में कतई नहीं आईं तथा 1998 में एन.डी.ए. की सरकार ने “न्यूतिलियर टेस्ट” करने का फैसला किया, पाश्चात्य देशों द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद।

यह रुख भारत की उस ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुरूप है जिसमें वह महाशक्तियों के दबाव का प्रतिकार करता आया है। नेहरू द्वारा शीत युद्ध के गुटों में शामिल होने से इनकार करने से लेकर इंदिरा गांधी द्वारा 1971 संकट के दौरान विरोध जताने और 1998 में पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु परीक्षणों को आगे बढ़ाने तक, यह प्रवृत्ति जानी पहचानी रही है। हर बार, भारत ने बाहरी दबाव को आत्मनिर्भरता जताने और दीर्घकालिक रणनीति को फिर से गढ़ने का अवसर बनाया है।

इसी भावना के तहत, मोदी सरकार इस टैरिफ वृद्धि को कोई गंभीर झटका नहीं बल्कि एक उत्प्रेरक के रूप में ले

रही है। अमेरिकी व्यापार आदेशों को बाध्यकारी न मानकर भारत यह संकेत दे रहा है कि वह अल्पकालिक कठिनाइयों को सहने को तैयार है, ताकि एक अधिक लचीली अर्थव्यवस्था बनाई जा सके - जो घरेलू मांग पर आधारित हो और जिसकी वैश्विक साझेदारियों में विविधता हो।

बुधवार से प्रभावी हुए 50 प्रतिशत टैरिफ का असर अमेरिका को होने वाले भारत के 45 अरब डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा, जिसमें केवल दवाएं, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिया गया है। वस्त्र, रत्न, झींगा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों के लिए यह वृद्धि कमजोर होती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बाढ़

सुकमा, 28 अगस्त । छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लगातार बारिश से उफान पर आई शबरी नदी और नालों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर गौदम नाला के पास 48 घंटे से फंसी बस में सवार यात्रियों को जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की

■ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 48 घंटे से फंसी बस के यात्रियों को बचाया गया। अब तक 2000 नागरिकों का पुनर्वास किया जा चुका है।

टीमों ने नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी 6 की गई।

जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। अब तक जिले के विभिन्न प्रभावित इलाकों में 22 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहाँ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश, निवेशक राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें : मुख्यमंत्री

बिजली-पानी-रोजगार क्षेत्र में हमने लिए हैं अभूतपूर्व निर्णय : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि समृद्ध, सशक्त और सर्वापरि राज्य बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने उधिमयों से आल्हान किया कि उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें। शर्मा गुरुवार को जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन से राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा कि उद्योगों को अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान मिनरल पॉलिसी, रीको प्रत्यक्ष आवंटन नीति, डेटा सेंटर नीति, वस्त्र एवं परिधान नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जैसी नीतियां जारी की गईं। शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देशभर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

देश के कुल खनिज ब्लॉक आवंटन का 20 प्रतिशत अकेले राजस्थान से हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट-2047 को मंजूरी दी है। यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजस्थान के सुनहरे



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित किया।

भविष्य का खाका है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 सौर परियोजनाओं को मंजूरी, नई भूमि आवंटन नीति, पंच गौरव जैसे नवाचारों एवं निर्णयों से ऊर्जा एवं उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। जोधपुर-पाली औद्योगिक गलियारा, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 19 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में

50,000 प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा वस्त्र, कृषि, इंजीनियरिंग और ऑटो क्लस्टर उद्योगों पर केंद्रित यह परियोजना राजस्थान को औद्योगिक मानचित्र पर नया स्थान दिलाएगी। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 जारी की गई है, जो 2030 तक प्रदेश के अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 125 गीगावाट के स्तर तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है तथा 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने

■ “राइजिंग राजस्थान समिट में राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है।”

कहा कि हमने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान’ से प्रेरणा लेते हुए ‘हरियालो राजस्थान’ की शुरुआत की है। अभियान के तहत 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है तथा अब तक हम 17 करोड़ से अधिक पौधे लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में असीमित अवसरों के साथ प्राकृतिक संसाधन एवं कुशल मानव संसाधन मौजूद हैं।

राज्य सरकार ने पिछले डेढ़ साल में पानी, बिजली, बुनियादी ढांचे और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। पेयजल और सिंचाई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, माही बांध योजना सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। साथ ही, हमने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, 1 हजार 300 गांवों को डामर

सड़कों से जोड़ना, मिसिंग लिंक रोड का निर्माण, जयपुर एयरपोर्ट का विस्तार सहित विभिन्न कार्यों से राज्य में विकास के नए मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं।

ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा तथा ट्रांसमिशन तंत्र को विकसित करने से इस क्षेत्र में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। हमारा संकल्प है कि हम किसान को 2027 तक दिन में बिजली देंगे।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि राजस्थान सरकार सुशासन का पर्याय बन चुकी है। वर्तमान सरकार जिम्मेदारी, जवाबदेही और उत्तरदायित्व के साथ कार्य कर रही है। यह पहला ऐसा राज्य है, जिसने अपने कार्यकाल के शुरुआत में ही निवेश समिट का आयोजन किया, साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देते हुए हरियालो राजस्थान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसे नवाचार भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार चार गुना शक्ति के साथ राजस्थान को आगे ले जा रही है। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहानी गैस सुरेश पी. मंगलानी, निदेशक एवं सहसंस्थापक एस.ए.ई.एल. इंडस्ट्रीज लि. सुखवीर आवला सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने समिट में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग अजिताभ शर्मा सहित बड़ी संख्या में उद्यमी और गणपत्याम मौजूद रहे।

जेल में फिर मिला मोबाइल और सिम

जयपुर। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल और सिम मिलने का रिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर जेल में मोबाइल और सिम मिलने से हड़कंप मच गया। जेल में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल और सिम लावारिस हालत में मिले हैं। इस संबंध में जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। थानाधिकारी बन्नालाल ने जेल अधीक्षक की ओर से मामला दर्ज करवाया है कि 27 अगस्त को जेल प्रशासन की ओर से सघन तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान दो नंबर वार्ड के बैरक नंबर 2 में टॉयलेट के पास एक सिल्वर कलर का छोटा कीपैड मोबाइल और सिम मिली है। इस पर जेल कर्मचारियों ने उच्चाधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी।

करीब 38 हजार रोगियों ने आरजीएचएस योजना के तहत उपचार प्राप्त किया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि जिन अस्पतालों ने उपचार बंद कर रखा है, उनके प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद जारी है।

हमारा प्रयास है कि सभी अस्पताल योजना के तहत सेवाएं उपलब्ध करवाएं। निजी अस्पतालों व सभी हितधारकों से चर्चा कर योजना में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। गड़बड़ी पर अंकुश लगाकर योजना का निबांध संचालन विभाग की प्राथमिकता है।

■ राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल का कहना है कि, “जिन अस्पतालों ने आर.जी.एच.एस. में उपचार बंद कर रखा है, उनके प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद जारी है। हमारा प्रयास है कि सभी अस्पताल योजना के तहत सेवाएं उपलब्ध करवाएं।”

ज्यादातर निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत सुचारु रूप से उपचार मिला। उन्होंने बताया कि करीब 350 अस्पतालों में ओपीडी, डे केयर एवं आईपीडी में रोगियों ने उपचार प्राप्त किया। प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध सभी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत उपचार मिल रहा है।

राठौड़ ने कहा कि निजी अस्पतालों के साथ-साथ राजकीय चिकित्सा संस्थानों में भी योजना के तहत उपचार के लिए सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि जहां भी निजी अस्पतालों में उपचार बंद हों, वहां राजकीय चिकित्सा संस्थानों में रोगी सुगमता से उपचार प्राप्त कर सकें। विगत 4 दिवस में

शाही ठाठ-बाट के साथ जयपुर भ्रमण पर निकले गणेशजी महाराज

मोतीढूंगरी मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा में 50 से अधिक झांकियां शामिल हुईं

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। मोती ढूंगरी गणेश जी मंदिर से श्री गणेश जन्मोत्सव के अंतर्गत गज पूजन के साथ 38वीं शोभायात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आरती कर शोभायात्रा को रवाना किया। यह पारंपरिक शोभायात्रा गढ़ गणेशजी मंदिर तक निकाली जाती है।

■ ऑपरेशन सिंदूर एस 400 मिसाइल की तर्ज पर निकाली गई शोभायात्रा रही आकर्षण का केन्द्र



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोतीढूंगरी गणेश मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा को रवाना किया। इस दौरान “ऑपरेशन सिंदूर” थीम पर सजाई गई झांकी आकर्षण का विशेष केन्द्र रही।

किया गया। भव्य शोभायात्रा में राम मंदिर में गर्णेशजी का तांडव नृत्य, रामलला के दर्शन, राम-रावण युद्ध, महाभारत का लेखन, शिव-पार्वती के प्रसंग, माता वैष्णो देवी दरबार की झांकी निशान ध्वज लेकर मौजूद रहे। इसके चार बजे मोती ढूंगरी से रवाना हुई जो मोती ढूंगरी रोड, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार से गणगौरी बाजार होते हुए ब्रह्मपुरी से नाहरगढ़ की पहाड़ी पर विराजमान गढ़ गणेश मंदिर पर समाप्त हुई। इस शोभायात्रा के साथ मोती ढूंगरी मंदिर के नौ दिन के गणेश जन्मोत्सव का समापन हुआ। शोभायात्रा के संयोजक भानु प्रताप ने बताया कि गुलाबी नगरी की यह

परंपरा हर साल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। इस बार शोभायात्रा में भक्तों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों अनुभव मिलता है। शोभायात्रा में सबसे आगे हाथी पर गामा पहलवान निशान ध्वज लेकर मौजूद रहे। इसके पीछे ऊंट-घोड़े और बैड बाजे के साथ चलते रहे। इस बार शोभायात्रा में 50 से अधिक झांकियां शामिल हुईं। पारंपरिक हाथी-घोड़े-ऊंट के लवाजमे से लेकर धार्मिक, ऐतिहासिक और समकालीन प्रसंगों को दर्शाती झांकियां सजाई गईं। इसमें ऑपरेशन सिंदूर और एस-400 मिसाइल की झांकी भी शामिल हुई। झांकियों में भगवान गणेश के विभिन्न

स्वरूपों के साथ-साथ अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन, राम-रावण युद्ध, महाभारत का लेखन, शिव-पार्वती के प्रसंग, माता वैष्णो देवी दरबार, महाकाल, छत्रपति शंभाजी महाराज, केदारनाथ धाम, शेखावाटी की सांस्कृतिक झलक और संत परंपराओं को भी प्रदर्शित किया गया। मंदिर समिति के अनुसार, भगवान गणेश की झांकियां स्वचालित तकनीक से भी सजाई गईं। इनमें गणेशजी का तांडव नृत्य, रिद्धि-सिद्धि संग नृत्य, मृषक पर सवारी, महाकाल रूप, और मोबाइल की लत से दूर रहने का संदेश जैसी झलकियां प्रमुख रही। एक झांकी में भगवान शंकर की पीठ पर गणेशजी सवारी करते हुए दिखाए गए।

‘नेता प्रतिपक्ष जूली की सहमति से 29 के बजाय 28 को रखी सर्वदलीय बैठक, फिर भी कांग्रेस ने किया बहिष्कार’

विधानसभा के मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को बुलाई थी यह सर्वदलीय बैठक

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू रूप से चलने के लिए गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कांग्रेस ने यह कहते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया कि यहां एक तरफा फैसला लिए जाते हैं।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक 2 सितंबर को होगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे।

वहीं दूसरी ओर बैठक के बहिष्कार पर सत्ता पक्ष ने कहा कि, विपक्षी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सर्वदलीय बैठक से पहले सभी पक्षों से सहमती ली जाती है। आज की डेट टीकाराम जूली से पूछकर ही तय की गई थी। वे 29 अगस्त को आने में असमर्थ थे, इसलिए जूली के कहने पर 28 अगस्त डेट तय की गई। अचानक उन्होंने सूचना दी कि वे और उनके सचेतक भी नहीं आएंगे। ऐसा करना मैदान छोड़ने वाली बात हुई। गर्ग ने कहा कि जानबूझकर बहिष्कार किया है। इसके कारण अभी तक हमको समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की आपस की लड़ाई, डोटसरा वर्सेस जूली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।

गर्ग ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है,

■ सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि, “नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अचानक सूचना दी कि वे और उनके सचेतक बैठक में नहीं आएंगे। ऐसा करना मैदान छोड़ने वाली बात हुई। मुझे लगता है कि कांग्रेस की आपस की लड़ाई, “डोटसरा वर्सेस जूली” की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।”

इसकी निंदा करते हैं। जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विधानसभा को लेकर शुरुआत से ही भाजपा सरकार की मंशा अच्छी नहीं रही है। विधानसभा अध्यक्ष चाह रहे हैं कि सत्र लम्बा चले, लेकिन सरकार चाह रही है कि कुछ दिन में ही विधानसभा सत्र खत्म हो जाए, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित न हो सके। विधानसभा में भी कई वाक्ये ऐसे हुए हैं जो एक पक्षीय रहे। हमारे विधायक नरेन्द्र बुढ़निया को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ दिन में ही हटा दिया गया। इतने वरिष्ठ सदस्य के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। जूली ने कहा कि

विधानसभा में सवालों के जवाब पहले जनता के लिए पोर्टल पर अपलोड होते थे, जो इस बार अपलोड नहीं किए गए। क्या सरकार को कोई डर है? जूली ने कहा कि इसी प्रकार जिलों में हमारे प्रधानों, प्रमुखों, चेरयमेंटों को चुन-चुनकर हटाया जा रहा है। सरकार के एक विधायक ने जनता के बीच कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में सभी

प्रधानों को हटाकर भाजपा के प्रधान बनाए हैं। यानी इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। यही कारण है कि संवैधानिक बाध्याताओं के बावजूद राज्य में पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय के चुनाव भी सरकार नहीं करवा रही और हाईकोर्ट से स्ट्रे लेकर आ रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारी सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मई 2020 में सभी 200 विधायकों और 25 सांसदों की बैठक लेकर उनकी बात सुनी थी। यहां केवल भाजपा विधायकों, सांसदों और जिनको जनता ने नकार दिया उन हारे हुए प्रत्याशियों से बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। ऐसी एकतरफा अप्रोच के कारण आज कांग्रेस पार्टी ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। हम सदन की पहले दिन की बैठक में भाग लेंगे। 2 सितंबर को हमारे विधायक दल की बैठक है जिसमें हमारे प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री समेत सभी के एक विधायक ने जनता के बीच कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में सभी

उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया

जयपुर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एसआई भर्ती परीक्षा - 2021 को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। क्योंकि करीब 500 लोग नकल माफिया के साथ सौदा कर परीक्षा में पास हुए। ये लोग पुलिस जैसे सेवेदनशील विभाग में एसआई बनकर जनता के साथ क्या न्याय करते एवं कैसे कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग देते। मैंने पहले दिन ही एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की थी, क्योंकि मेरे पास एसआई पेपर लीक होने के पक्के सबूत थे। मैंने पूर्ववर्ती सरकार के समय एसओजी को ये सभी सबूत दिए। मैंने जैसे ही सबूत दिए वे सही निकलते गये, जिसके लिए आभारन किए, लेकिन पूर्व सरकार की नकल माफिया से सांठगांठ थी।

जवाहर कला केन्द्र में “चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट” का शुभारंभ

जयपुर। जयपुर के जवाहर कला केन्द्र स्थित अलंकार आर्ट गैलरी में संयुक्त कला प्रदर्शनी “चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट” का भव्य शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों - निधि चौधरी, निकिता



चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों निधि चौधरी, निकिता टाटेर, पारिधि जैन और शगुन अग्रवाल की ओर से जवाहर कला केन्द्र में संयुक्त कला प्रदर्शनी “चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट” प्रदर्शित की गई है।

को अभिव्यक्त करती हैं। उनकी कला श्रृंखला ए जर्नी इन्वॉड आत्मा-वेषण और आत्मसंवाद की गहरी झलक देती है। शगुन अपने पॉइंटकार्ट ‘शेरदिल्ली’ के जरिये भी व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को जोड़ने का कार्य करती हैं। यह प्रदर्शनी 31 अगस्त 2025 तक प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी।

वर्तमान में 22 फरवरी 2022 तक की कट ऑफ डेट के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कनेक्शन देय है। राज्य में फिलहाल 78 हजार 498 कृषि कनेक्शन लंबित हैं, जिनमें डिमाण्ड नोट जमा किए जा चुके हैं।

■ विकेंद्रित सौर संयंत्रों से संबद्ध फीडरों में तुरन्त जारी होंगे कृषि कनेक्शन

मांग पत्र जारी किए जा सकेंगे। मांग पत्र जमा होने के बाद आवेदकों को तुरंत प्राथमिकता से कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। मौजूदा समय में कृषि कनेक्शन नीति-2017 के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन के आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा घोषित निर्धारित अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) के अनुसार डिमांड नोट जारी किए जाते हैं। मांग पत्र

■ चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन

टाटेर, पारिधि जैन और शगुन अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया।

इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों और कला प्रेमियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी राजस्थान की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई है, साथ ही विश्वभर की यात्राओं से मिली प्रेरणाओं को भी दर्शाती है। शगुन अग्रवाल, जो मनोविज्ञान में प्रशिक्षित हैं और बचपन से कला से जुड़ी रही हैं, अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से बदलते मानसिक परिदृश्यों

मुख्यमंत्री ने किसान हित में लिया निर्णय

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय किया है। अब पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े 33/11 केवी सब स्टेशन क्षेत्रों में अलग से प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कृषि कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए कृषि कनेक्शन नीति-2017 में संशोधन को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के तीनों विधुत वितरण निगमों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय के पश्चात अब ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता के अनुसार 33/11 केवी से निकलने वाले फीडरों पर कृषि कनेक्शन के लिए आवेदकों को पृथक् से प्राथमिकता से



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की, वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए।

‘सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह भी कहा कि अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी

जयपुर, 28 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क, बायपास, आरओबी और आरयूबी जैसी जनउपयोगी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में घंटिया सामग्री का उपयोग पाए जाने और अकारण देरी पर कौन्ट्रक्टर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उससे वसूली की जाएगी। साथ ही, अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त

- मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मानचून में क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे कराकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिये।**

कार्यवाही होगी।

मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2025–26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानचून

के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे करवाकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करवाया जाए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को बेहतर सड़क निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सूची संधारित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के

लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सड़क, बायपास आदि के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण पर उन नीतियों पर विचार करें जिसमें विभाग को भविष्य में राजस्व की बढ़ोतरी हो। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय प्रोजेक्ट्स एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय

चर्चा है कि जेडीयू 102, भाजपा 101, चिराग पासवान 20, मांझी व उपेन्द्र कुशवाह 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे

- कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा तो लाभभग तय हो गया है, पर कौन सी पार्टी किस सीट से लड़ेगी, इस पर चिंतन जारी है।**

गठबंधन की सीट शेर्यरिंग की तस्वीर अब काफी साफ हो गई है। लेकिन कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी इसका मंथन आगे होगा। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए थे। इस बीच अब सीटों का ये आंखड़ा आया है। जेडीयू को अधिक सीटें देकर यह बताते की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।

छत्तीसगढ़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
2000 से अधिक लोगों का अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया गया है। शिविरों में रहने, खाने और सोने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है।

अमेरिकी वीजा की अवधि घटाई जाएगी?

वाशिंगटन, 28 अगस्त। अमेरिकी प्रशासन अपने वीजा नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है और अगर ये नियम स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे अमेरिका में रह रहे वीजा धारकों की समयावधि घट जाएगी। इससे वहां रह रहे लोगों खासकर छात्रों को अपने देश जल्द वापस लौटना पड़ सकता है।

अमेरिकी गृह विभाग ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि ये प्रस्तावित नियम अगर स्वीकार हो जाते हैं तो इससे वीजा के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और शासन की इन व्यक्तियों की जांच और निगरानी करने को क्षमता बढ़ेगी। यह नियम कुछ ही तरह की वीजा श्रेणी पर लागू होगा और इस श्रेणी में विदेशी छात्रों

- अगर ऐसा हुआ तो वहां काम या पढ़ाई के लिए गए लोगों को जल्दी ही लौटना पड़ सकता है।**

को मिलने वाला वीजा भी शामिल है। अमेरिका के गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, “बहुत लंबे समय से, पिछले प्रशासनों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीजा धारकों को लगभग अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा होता है।” विदित हो कि सन 1978 से, यहां आने वाले विदेशी छात्रों को एच श्रेणी का वीजा एक खास अवधि के लिए दिया जाता रहा है। अन्य वीजा श्रेणी से भिन्न यह वीजा धारकों को बिना किसी अतिरिक्त जांच-पड़ताल के अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति देता है। अब अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि विदेशी छात्रों ने अमेरिकी उदारता का लाभ उठाया है और वे ऐसे “स्थायी” छात्र बन गए हैं, जो अमेरिका में रहने के लिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में स्थायी रूप से खुद का नामांकन किए रहते हैं।

बिहार में घुसे तीन संदिग्धों पर 5 0 हजार का इनाम घोषित

तीनों पाकिस्तानी संदिग्ध नेपाल की सीमा से बिहार में घुसे हैं राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है

- इस घटनाक्रम के बाद राहुल की वोट अधिकार यात्रा में भी बदलाव किया गया है अब वे खुली जीप की बजाय बंदगाड़ी से यात्रा कर रहें हैं।**

शामिल हैं। पुलिस की ओर से इन तीनों संदिग्धों के नाम, तस्वीर सार्वजनिक कर दिये गये हैं।

पुलिस हेक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है।

वहीं मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकियों पर 50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। बिहार में घुसे तीनों आतंकियों का पासपोर्ट भी सामने आया

मोदी जापान और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
देशों के प्रमुख से होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर मैं 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। हम इस यात्रा के दौरान अपनी वैश्विक रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान देंगे। यह यात्रा हमारे सभ्यतागत बंधनों और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का भी अवसर

होगी जो हमारे लोगों को परस्पर जोड़ते हैं।(पीएम ने कहा कि जापान से मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाऊंगा। भारत एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है। सात साल में चीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ नजदीकी बंद।कर मेक इन इंडिया पहल के लिए समर्थन जुटाएंगे।

‘वैश्विक नेताओं से निजी ...

- इसके लिए भारत पर हर तरफ से दबाव डाला जा रहा है। कभी टैरिफ बढ़ाकर कभी एच वन-बी वीजा के नाम पर तो कभी ऑपरेशन सिंदूर व सीज़फायर पर दावे करके तो कभी रुस -यूक्रेन जंग को मोदी की जंग बताकर।**
- प्र.मंत्री मोदी ने भी इस दबाव को स्वीकार किया और कहा कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, हम उसे सहन करेंगे पर हम किसानों, पशुपालकों व लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।**

चाहता है कि भारत कृषि बाज़ार को उसके उत्पादों के लिए खोले जो कि कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मतलब होगा भारतीय किसानों की बर्बादी।

एक वरिष्ठ राजनयिक ने जब पूछा गया कि अमेरिका भारत के पीछे क्यों पड़ा है, तो उन्होंने कहा: ये सब अर्थव्यवस्था के कारण है।”

वाइट हाउस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को इस बात की पुष्टि भी कर दी कि “यह केवल रूसी तेल के बारे में नहीं है।”

बेसेंट ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौता वार्ताओं में केवल “दिखावा” किया है।

नवरो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “महान नेता” बताया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा, वह इस सिद्धांत

काहता है कि भारत कृषि बाज़ार को उसके उत्पादों के लिए खोले जो कि कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मतलब होगा भारतीय किसानों की बर्बादी।

एक वरिष्ठ राजनयिक ने जब पूछा गया कि अमेरिका भारत के पीछे क्यों पड़ा है, तो उन्होंने कहा: ये सब अर्थव्यवस्था के कारण है।”

वाइट हाउस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को इस बात की पुष्टि भी कर दी कि “यह केवल रूसी तेल के बारे में नहीं है।”

बेसेंट ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौता वार्ताओं में केवल “दिखावा” किया है।

नवरो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “महान नेता” बताया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा, वह इस सिद्धांत

भारत ने ट्रंप की ‘‘टैरिफ ...

- पर, यह भी सच है कि, दीर्घकाल की दृष्टि से, भारत की यह सामना करने की नीति लाभकारी ही रहेगी, पर तत्कालिक रूप से आर्थिक पीड़ा जरूर होगी, क्योंकि भारत के अमेरिका को निर्यात होने वाले 45अरब डॉलर के माल पर भारी संकट आयेगा, कुछ रोजगार भी खत्म हो जायेंगे ।**

गति पर विवाद है, लेकिन यह सुधार अनुपालन को सरल बनाता है और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे सकता है। यह भारत के सुधार एजेंडे की निरंतरता को भी दर्शाता है, जिससे निवेशकों को यह परीसा मिलता है कि बाहरी उथल-पुथल से आंतरिक नीतिगत प्रगति बाधित नहीं होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गोबा के नेतृत्व में दो उच्चस्तरीय समितियाँ नियामक छूट और संरचनात्मक सुधारों के खके तैयार कर रही हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को विकास को मजबूत करने और जीवन स्तर सुधारने के उपाय सुझाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी अर्थशास्त्रियों को विश्वास है कि यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे और मॉड्रिक नीति अनुकूल बनी रहे, तो वित्त वर्ष 26 में 6.5 प्रतिशत विकास दर हासिल की जा सकेगी। ये दोनों पहलू नीति प्रतिक्रिया के दो स्तरों को दर्शाते हैं – एक जो रणनीतिक दृष्टिकोण और संरचनात्मक सुधार प्रदान करता है (गोबा के नेतृत्व वाली समितियाँ), और दूसरा जो समयबद्ध, तथ्यों पर आधारित आर्थिक

सलाह देती है यानि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। यह दिखाता है कि भारत बाहरी झटकों के जवाब में दीर्घकालिक योजना और त्वरित आर्थिक सलाह दोनों को सक्रिय रूप से जुटा रहा है।

अल्पकाल में, टैरिफ वृद्धि से नुकसान होगा। श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यातकों को दबाव का सामना करना पड़ेगा, और वैकल्पिक बाजार विकसित होने से पहले व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है। फिर भी, मोदी सरकार इस अस्थिरता को एक उदत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है। घरेलू खपत पर दंव लगाकर, सुधारों में तेजी लाकर और वैश्विक साझेदारियों में विविधता लाकर, नई दिल्ली टैरिफ झटके को दीर्घकालिक लाभ में बदलने की रणनीति अपना रही है। हालांकि इसका लाभ असमान रूप से मिलेगा। अल्पकालिक दर्द टालना संभव नहीं है। लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसका लाभ एक अधिक मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था हो सकती है – जो वाशिंगटन को व्यापार नीति की अनिश्चितताओं से कम प्रभावित हो, और अपनी घरेलू मांग व विविध वैश्विक संबंधों पर अधिक आधारित हो।

^[1] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वलन प्रेस, एच-150 , रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुघर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाउस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्यद मैने रोड आर्यद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रत भवन, सुग्री नाका के पास, अजमेरा। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोरा। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डोर्नसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोर्नसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600